International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology
Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099 (www.ijsrset.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRSET

कौशल विकास एवं बेरोजगारी :

भानुप्रकाश भास्कर
प्रवक्ता (अर्थशास्त्र), सर्वोदय इ. का. पियरगाँव, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 8, Issue 5
Page Number : 343-345

Publication Issue :
September-October-2021

Article History
Accepted : 10 Sep 2021
Published: 20 Sep 2021

ABSTRACT

व्यापक स्तर पर बेरोजगारी का प्रमुख कारण युवाओं को अपर्याप्त और गुणवत्ताविहीन कौशल प्रशिक्षण देना है। श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह रेखांकित होता है कि सिर्फ 7 प्रतिशत युवा ही औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। हाल ही में जारी आँकडों से मिली जानकारी के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का सिर्फ 2.3 प्रशित है। औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करता है जबकि यही आँकड़ा ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, जर्मनी मे 75 प्रतिशत, अमेरिका मे 52 प्रतिशत, जापान मे 80 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया 96 प्रतिशत है। दूसरी ओर हाल में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 48 प्रतिशत भारतीय नियोक्ता ऐसे है, जो खाली पड़ी रिक्तियों को भरने में कठिनाई का सामना करते है क्योंकि लोगों में आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण की कमी है।

सरकार की पहल : स्किल इंडिया कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2023 तक कम से कम 30 करोड़ लोगो को कौशल प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : यह कौशल भारत का ही हिस्सा है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधी शुक्त सरकार वहन करेगी। इसका प्रमुख कार्य लोगों को कम अवधि का प्रशिक्षण (150-300 घंटे का) प्रदान करता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले साझीदार कुछ प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करते है। वर्ष 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का निर्माण किया गया। इस मंत्रालय के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षण प्रक्रिया मे बेहतर तालमेल स्थापित करना, परिणामो का मूल्याकन एवं प्रमाणन तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का निर्माण एवं विकास करना था। ज्ञात है कि आई टी आई को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिये एक यावश्यक घटक माना गया है। संकल्प और स्ट्राइल कार्यक्रम जिला-स्तरीय स्किलिंग परितंत्र पर केंद्रित है और स्ट्राइब योजना जिसका उद्देश्य आई. टी.आई के प्रदर्शन मे सुधार करना है, एक अन्य महत्वपूर्ण कौशल निर्माण आयाम है।

कौशल विकास के अतर्गत सरकार ने गरीब व वंचित युवाओं को प्रशिक्षित करके बेरोजगारी की समस्या और गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का उद्देश्य उचित प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओ मे आत्मविश्वास को लाना है जिससे की उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकारी, निजी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थाये भी सम्मिलित' होकर करेगी। कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत मे बेरोजगारी की समस्या के निवारण मे सहायता।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

- **उत्पादकता में वृद्धि।**
- **भारत में गरीबी ख़त्म करने मे सहायक।**
- **भारत में छिपी हुई योग्यता को बढावा देने में सहायक।**
- **राष्ट्रीय आय के साथ-साथ प्रति व्यक्ति में वृद्धि।**
- **लोगो की जीवन निर्वाह आय में वृद्धि।**
- **भारतीयों के जीवन स्तर मे सुधार ।**

कौशल विकास अभियान को जागरुकता अभियानों के साथ सभी लोगों को उनके हुनर मे कुशल करके भारत से वह–आयामी समस्याओ का निराकरण करना है। प्रधानमन्त्री श्री नरेद्र मोदी के शब्दों मे मैं भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिये पूरे राष्ट्र को प्रतिज्ञा करने के लिये आहवन करता हूँ। स्किल इंडिया का कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2023 तक 30 करोड लोगो को कौशल प्रदान करना है। रखा गया था लेकिन वर्ष 2018 तक इस योजना के अंतर्गत केवल 25 मिलियन लोगों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसका प्रमुख कारण का उचित प्रबन्धन न किया जाना तथा प्रशिक्षण हेतु कम लोगो द्वारा आवेदन करना था जिसकी वजह से उचित मात्रा में वित्त का व्यय नहीं किया जा सका, को माना जा सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। किन्तु प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार की प्राप्ति दर मे तेजी में कमी आई है।

भारत में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के मध्य भी रोजगार की दर कम है, इसका प्रमुख कारण पर्याप्त और गुणवत्तापरक प्रशिक्षण का प्राप्त न होना रहा है। कम अवधि के प्रशिक्षण में सीखने की संभावनाएं सीमित होती है। जहाँ अभियांत्रिकी के विद्यार्थी किसी विषय के लिये चार वर्ष का समय लेते है वही उसी विषय के समरूप कोई कौशल प्रशिक्षण कुछ माह में प्राप्त नही किया जा सकता है।

उद्यमिता कौशल की कमी: सरकार का दृष्टिकोण था कि प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग स्वरोजगार की ओर मुडेंगे, इससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। किन्तु^{२ळ} प्रतिशत लोगों ने ही सिर्फ अपने व्यवसाय आरम्भ किये जबकि इनमें से भी सिर्फ दस हजार लोगो नेही मुद्रा तन्त्र हेतु आवेदन किया।

विद्यार्थियों में कम आकर्षण: कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे – आई. टी. आई तथा पोलिटेक्निक में इनकी क्षमता के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ। इसका प्रमुख कारण युवाओं के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर सीमित जागरुकता को माना जा सकता है।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि यदि शिक्षा पर खर्च सीमित बना रहता है तो स्किल इंडिया कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देने में नही हो सकेगा। इसके लिये मूलभूत स्तर पर विद्यार्थी के भीतर कौशल शिक्षा के प्रति रुझान को पैदा करना आवश्यक है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को प्रशिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन तथा इन संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही साथ ऐसी विधियों एवं तकनीकी का सृजन करना चाहिए। भारत को चीन, जापान, जर्मनी, प्राजील, सिंगापुर आदि के व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए।

निष्कर्ष- मोजूदा समय में भारत मे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इस समस्या के लिये एक बड़ी वजह भारत में कौशल विकास की कमजोर स्थिति को माना जा सकता है। भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम ने भी रोजगार वृद्धि के लिये अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नही किये है। भारत में कौशल विकास तथा बेरोजगारी की समस्या के मूल मे स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की अनुपस्थिति तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन है। भारत विभिन्न विकसित देशों एवं पूर्वी एशिया के देशो से भारत प्रेरणा ले सकता है साथ ही साथ भारतीय स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी बड़ी युवा आबादी को जनसाख्यिकी लाभांश में तब्दील कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : ओझा अश्विनी कुमार।
2. भारतीय जनगणना 2011 ।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ।
4. विश्व बैंक 2013 की रिपोर्ट ।
5. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना ।